भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3491

उत्तर देने की तारीख - 11/08/2025

सोमवार, 20 श्रावण, 1947 (शक)

ई-कॉमर्स उद्यमिता प्रशिक्षण

†3491. डॉ. कडियम काव्य:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वारंगल के ग्रामीण युवाओं को ई-कॉमर्स उद्यमिता में प्रशिक्षण करने संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तेलंगाना में 2024-25 में लाभार्थियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) बाजार तक पहुँच के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ क्या साझेदारियाँ की गई हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से तेलंगाना राज्य के वारंगल सहित विभिन्न जिलों में ई-कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता विकास में युवाओं के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की है। इन पहलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निस्बड ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता आधारित कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) संचालित किए हैं। व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के उपयोग संबंधी मॉड्यूल ईडीपी और ईएसडीपी पाठ्यक्रमों में एकीकृत किया गया है।

(ii) संकल्प स्कीम के अंतर्गत क्षमता निर्माण के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को मजबूत करना, इनक्यूबेशन सहायता, मार्गदर्शन और सहायता - कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(एमएसडीई) के तहत निस्बड ने आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के सहयोग से समाज के विभिन्न कमज़ोर वर्गों के उद्यमिता इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन और सहायता के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना का सृजन, पोषण और संवर्धन करना है। इस संस्थान ने वर्ष 2022-23 में वारंगल जिले में इस परियोजना के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से 50 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया है।

(iii) उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक परियोजना - एमएसडीई के तहत निस्बड ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से 10 राज्यों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए एक प्रायोगिक परियोजना लागू की है जिसका उद्देश्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम, मार्गदर्शन और सहायता के माध्यम से लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता की भावना का सृजन, पोषण और संवर्धन करना है। संस्थान ने वर्ष 2022-23 में वारंगल जिले में परियोजना के माध्यम से 120 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया है।

(iv) एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् निस्बड और आईआईई के माध्यम से, मार्च 2024 से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक स्कीम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कौशलीकरण और उद्यमिता घटक को क्रियान्वित कर रहा है। यह परियोजना देश भर के 15 राज्यों में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं। दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, 25 वीडीवीके के कुल लक्ष्य में से 25 वीडीवीके स्थापित किए जा चुके हैं और तेलंगाना राज्य में 1,461 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(v) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सहयोग से एमएसडीई के अंतर्गत निस्बड, अपनी प्रमुख पहल, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर उद्यमिता संबंधी उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सौर उद्यमिता के क्षेत्र में उभरते और मौजूदा उद्यमियों को प्रोत्साहित करके और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करके रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना, उद्यमियों को सशक्त बनाना और उनके लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है। निस्बड ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान तेलंगाना राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत 30 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया है।

(ग) एमएसडीई के अंतर्गत निस्बड ने उद्यमिता और आजीविका विकास हेतु डिजिटल मार्केटिंग लिंकेज को बढ़ावा देने और बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ सहयोग किया है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य युवाओं को आवश्यक डिजिटल कौशल से सुसज्जित करके उन्हें अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाने और बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना है। इस संबंध में निस्बड द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा इस प्रकार है:

संगठन	**समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि**	**उद्देश्य**
डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)	13.08.2024	उद्यमिता और आजीविका विकास के लिए डिजिटल कॉमर्स का लाभ उठाने हेतु सहयोग करना। यह ओएनडीसी के नेटवर्क के माध्यम से कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और उद्यमशीलता गतिविधियों को समर्थन देने पर केंद्रित है।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)	13.08.2024	निस्बड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जीईएम खरीद को एकीकृत करने और जीईएम पोर्टल पर उद्यमियों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए।
मेटा (फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम)	04.09.2023	आज के गतिशील बाजार परिवेश में सफल होने के लिए महत्वाकांक्षी और वर्तमान लघु व्यवसाय मालिकों को डिजिटल मार्केटिंग कौशल संबंधी आवश्यक टूल्स, ज्ञान और संसाधन प्रदान करना।

इसके अलावा, उत्तर पूर्वी राज्य असम में, आईआईई जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक स्कीम, प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) को लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के जनजातीय समुदायों की आजीविका को उन्नत करना है, ताकि उन्हें लघु वनोपज (एमएफपी) के मूल्य संवर्धन के माध्यम से स्थायी आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके और उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया जा सके। पीएमवीडीवाई के तहत असम के आईआईई के वन धन विकास केंद्रों के उत्पादों को "त्रिसम" के रूप में ब्रांड किया गया है और व्यापक बाजार पहुँच के लिए स्विगी मिनी स्टोर्स और माईस्टोर जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया गया है।

इसके अलावा, उत्तर पूर्वी राज्य असम में, आईआईई जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की एक स्कीम, प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का

उद्देश्य लघु वनोपज (एमएफपी) के मूल्य संवर्धन और उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करके जनजातीय समुदायों को स्थायी आजीविका प्रदान करके उनकी आजीविका का उत्थान करना है। पीएमवीडीवाई के तहत आईआईई के वन धन विकास केंद्रों के उत्पादों को "त्रिसम" के रूप में ब्रांडेड किया गया है और व्यापक बाजार पहुँच के लिए स्विगी मिनी स्टोर्स और माईस्टोर जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया गया है।

*****